



Daily करेंट अफेयर्स

»» 05 अगस्त 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी का दौरा किया, ₹2,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और PM-किसान निधि जारी की।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त, 2025 को सुबह लगभग 11 बजे अपना वाराणसी दौरा शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ, उन्होंने मेहदीगंज में एक सार्वजनिक कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जहाँ उन्होंने लगभग ₹2,200 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये परियोजनाएँ सड़क, बिजली, पर्यटन, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य सेवा और शहरी बुनियादी ढाँचे सहित विविध क्षेत्रों में फैली हुई थीं।

- परिवहन और संपर्क क्षेत्र में, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी-भदोही और छितौनी-शूल टंकेश्वर सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ मोहन सराय-अदलपुरा खंड पर हरदत्तपुर में एक नए रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने दालमंडी, लहरतारा-कोटवा, गंगापुर और बाबतपुर में कॉरिडोर उन्नयन के साथ-साथ भीड़भाड़ कम करने के लिए लेवल क्रॉसिंग 22सी और खालिसपुर यार्ड पर ओवरब्रिज का भी उद्घाटन किया।

- बुनियादी ढाँचे में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि स्मार्ट पावर परियोजना का शुभारंभ था, जिसके तहत बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार के लिए

स्मार्ट वितरण और भूमिगत केबल बिछाने के लिए ₹880 करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया। इस कदम का उद्देश्य शहरी बिजली प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना और बार-बार होने वाली बिजली कटौती को रोकना है।

- आठ नदी तट घाटों के विकास, दुर्गाकुंड और कर्दमेश्वर महादेव सहित मंदिरों के जीर्णोद्धार और कालिका धाम के सौंदर्यीकरण के साथ सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यटन पर ज़ोर दिया गया। हरित शहरी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए करखियाँ में मियावाकी पार्क और शहीद उद्यान जैसी शहरी वानिकी पहल भी शुरू की गई।

Key Points:-

(i) शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, प्रधानमंत्री ने एक नए होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी, 53 स्कूल भवनों का उन्नयन किया और एक जिला पुस्तकालय का उद्घाटन किया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र और होमी भाभा कैंसर अस्पताल में सीटी स्कैनर और रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम जैसे उन्नत चिकित्सा उपकरण लगाकर स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे को मजबूत किया गया।

(ii) इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने PM-किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की, जिसके तहत देश भर के 9.70 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे ₹20,500 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जिनमें से लगभग ₹900 करोड़ वाराणसी के किसानों को लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को 7,400 से ज़्यादा सहायक उपकरण वितरित किए गए, जो कल्याणकारी योजनाओं का एक उदाहरण है।

(iii) प्रधानमंत्री मोदी ने श्रावण मास में बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन न करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनका मानना था कि इस पवित्र अवधि में उनकी

उपस्थिति से श्रद्धालुओं की भीड़भाड़ और असुविधा हो सकती है। उन्होंने गहरी आध्यात्मिक श्रद्धा और भक्ति व्यक्त की, और व्यक्तिगत इच्छा से ज़्यादा सार्वजनिक सुविधा पर ज़ोर दिया। अपने संबोधन के अंत में, उन्होंने "वोकल फ़ॉर लोकल" की भावना का समर्थन किया, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रकाश डाला और भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दृष्टिकोण की पुष्टि की।

2. PM मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2025 ने 3.53 करोड़ पंजीकरण के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।



अगस्त 2025 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार्षिक इंटरैक्टिव कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा (PPC)' एक ही महीने में 3.53 करोड़ वैध पंजीकरणों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। शिक्षा मंत्रालय और MyGov के तहत आयोजित यह कार्यक्रम छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में तनावमुक्त परीक्षा को बढ़ावा देता है।

● 2025 का संस्करण परीक्षा पे चर्चा (PPC) का 8वां संस्करण होगा, जिसे पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था। PPC शिक्षा मंत्रालय (MoE) के तहत एक पहल है, जहां प्रधानमंत्री परीक्षा के तनाव को कम करने और समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ सीधे संवाद करते हैं।

● इस वर्ष, PPC ने 3.53 करोड़ वैध पंजीकरणों के साथ एक नई वैश्विक उपलब्धि हासिल की, जिससे यह एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक बन गया। पंजीकरण MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए गए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत संचालित भारत का प्रमुख नागरिक सहभागिता पोर्टल है।

● नई दिल्ली में आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद उपस्थित थे।

Key Points:-

(i) केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि PPC के 2025 संस्करण को टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलाकर 21 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह शैक्षिक सुधार में जनता की बढ़ती भागीदारी के महत्व को दर्शाता है और विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

(ii) केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शासन में प्रौद्योगिकी के एकीकरण की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि PPC न केवल परीक्षा की तैयारी में मदद करता है, बल्कि छात्रों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और मानसिक स्वास्थ्य को भी मज़बूत करता है—जो मिशन लाइफ़ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) और डिजिटल इंडिया अभियानों के प्रमुख लक्ष्य हैं।

(iii) राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इस पहल को डिजिटल रूप से समावेशी बनाने के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की प्रशंसा की और इसे सहभागी शासन का एक मानक बताया। अनुभववात्मक शिक्षा, तनाव-मुक्त शिक्षा और रोटल लर्निंग से विश्लेषणात्मक सोच

की ओर बदलाव को बढ़ावा देकर, PPC राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) का एक प्रमुख उपकरण बन गया है।

3. आठ सहकारी समितियां एकजुट होकर 'भारत' टैक्सी सेवा शुरू करेंगी, दिसंबर 2025 तक 200 ड्राइवरों को शामिल करेंगी।



अगस्त 2025 में, आठ प्रमुख सहकारी समितियों ने मिलकर ₹300 करोड़ की अधिकृत पूंजी से मल्टी-स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की स्थापना की। "भारत" नाम से ब्रांडेड, इस सहकारी टैक्सी सेवा का लक्ष्य दिसंबर तक पूरे भारत में शुरू करना है, और चार राज्यों में 200 ड्राइवर पहले ही जुड़ चुके हैं।

- सहकारी उद्यम-मल्टी-स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड - को औपचारिक रूप से 6 जून 2025 को पंजीकृत किया गया था। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको), गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ), कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) सहित आठ प्रमुख सहकारी समितियों को एक साथ लाता है।

- सहकारी भागीदारों से पूरी तरह एकत्रित ₹300 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ, भारत सेवा की योजना बिना किसी सरकारी इक्विटी के बनाई गई है। इसका उद्देश्य ड्राइवर-प्रथम आय, सुरक्षित और किफायती यात्राएँ, और एक सहकारी मूल्य निर्धारण मॉडल प्रदान करना है, जिससे निजी राइड-हेलिंग दिग्गज ओला और उबर को चुनौती मिल सके।

- अब तक, चार प्रमुख राज्यों - दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र - से 200 ड्राइवरों को शामिल किया जा चुका है, जिनमें से प्रत्येक राज्य से 50 ड्राइवर हैं। अतिरिक्त सहकारी समितियों को शामिल करके ड्राइवर नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास जारी हैं।

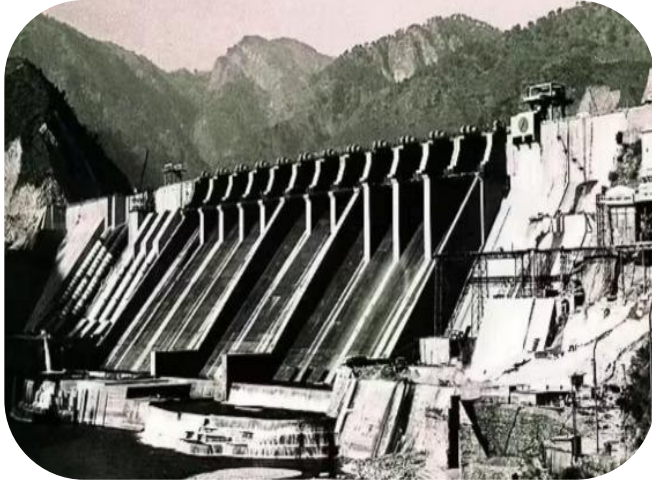
Key Points:-

(i) भारत राइड-हेलिंग ऐप विकसित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी भागीदार नियुक्त करने हेतु एक निविदा जारी की गई है। ऐप का विकास दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही, आईआईएम-बैंगलोर और अन्य प्रौद्योगिकी सलाहकार इस एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक अखिल भारतीय विपणन रणनीति तैयार कर रहे हैं।

(ii) यह पहल सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के अनावरण के बाद की गई है। यह नीति टैक्सी सेवाओं, पर्यटन, बीमा और रियल एस्टेट जैसे उभरते क्षेत्रों में सहकारी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए एक रणनीतिक ढाँचा है। इस नीति की घोषणा जुलाई 2025 में की गई थी।

(iii) सहकारी स्वामित्व मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि ड्राइवर और हितधारक लाभ को समान रूप से साझा करें और प्लेटफ़ॉर्म में निवेशित रहें। भारत को निजी एग्रीगेटर्स के लिए ड्राइवर-स्वामित्व वाले, पारदर्शी विकल्प के रूप में स्थापित किया गया है, जो पूरे भारत में सम्मान, आय सुरक्षा और समावेशी गतिशीलता सेवाओं को बढ़ावा देता है।

4. भारत ने जम्मू-कश्मीर में सावलकोट जलविद्युत परियोजना को पुनर्जीवित किया और जम्मू-कश्मीर के सबसे बड़े 1,856 मेगावाट संयंत्र को मंजूरी दी गई।



जुलाई 2025 में, भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर के रामबन ज़िले में चिनाब नदी पर लंबे समय से लंबित सावलकोट जलविद्युत परियोजना को गति प्रदान की। एनएचपीसी द्वारा शुरू की गई निविदा के साथ, 1,856 मेगावाट (मेगावाट) की इस परियोजना को भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बीच राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया है।

● मूल रूप से 1960 के दशक में केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा परिकल्पित और 1962-71 के बीच भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण की गई यह परियोजना दशकों तक निष्क्रिय रही। फरवरी 2018 में ही एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) प्रस्तुत की गई।

● अब, अप्रैल 2025 में सिंधु जल संधि (IWT) के स्थगित होने के बाद, राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (NHPC) ने 29 जुलाई, 2025 को पैकेज-1-योजना, डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की एक अंतरराष्ट्रीय निविदा जारी की है।

● रन-ऑफ-द-रिवर डिज़ाइन में 192.5 मीटर लंबा रोलर-कॉम्पैक्टेड कंक्रीट ग्रेविटी बांध, तीन डायवर्जन सुरंगें (965 मीटर, 1,130 मीटर और 1,280 मीटर), और 225 मेगावाट क्षमता वाले आठ टर्बाइनों वाला एक भूमिगत बिजलीघर (कुल 1,800 मेगावाट) शामिल है, साथ ही अनिवार्य पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 56 मेगावाट की एक सहायक इकाई भी है, जिससे स्थापित क्षमता 1,856 मेगावाट हो जाएगी। यह 2,977 क्यूमेक (गैर-मानसून) और 9,292 क्यूमेक (मानसून) बाढ़ डायवर्जन को संभालेगा।

Key Points:-

(i) DPR के अनुसार, लगभग 22,704 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली सावलकोट परियोजना का लक्ष्य सालाना 7,000 मिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न करना है। चालू होने के बाद, यह जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना बन जाएगी—जो 900 मेगावाट के बगलिहार संयंत्र को भी पीछे छोड़ देगी—और केंद्र शासित प्रदेश तथा उत्तरी भारत में ऊर्जा उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी।

(ii) सिंधु जल संधि (IWT) के निलंबित होने के बाद, भारत ने चिनाब नदी और अन्य पश्चिमी नदियों पर संप्रभुता का दावा किया है। सावलकोट का पुनरुद्धार एक रणनीतिक ऊर्जा पहल और एक कूटनीतिक संकेत दोनों है, जो जल संसाधनों पर भारत के नियंत्रण को मज़बूत करता है।

(iii) इस परियोजना को 'राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना' का दर्जा भी दिया गया है, जिससे स्वीकृतियाँ सुगम हो गई हैं। ऊर्जा के अलावा, यह बाढ़ नियंत्रण, कार्यान्वयन के दौरान रोज़गार सृजन और रामबन तथा उधमपुर ज़िलों के आर्थिक उत्थान में भी सहायक है।

5. खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) के अंतर्गत 7 उत्कृष्टता केंद्रों (COES) को मान्यता दी।



अगस्त 2025 में, खान मंत्रालय (MoM) ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) के अंतर्गत सात प्रमुख संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र (CoE) के रूप में मान्यता दी, जिनमें चार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और तीन शीर्ष अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रयोगशालाएँ शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना और रणनीतिक खनिज संसाधनों में भारत की आत्मनिर्भरता को मज़बूत करना है।

● यह मान्यता परियोजना अनुमोदन एवं सलाहकार समिति (PAC) द्वारा अनुमोदन के बाद प्रदान की गई, जिसकी सह-अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव वी.एल. कांता राव और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने की। बैठक में उन संस्थानों को अंतिम रूप दिया गया जो महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और प्रसंस्करण में नवाचार का नेतृत्व करेंगे।

● ये सात उत्कृष्टता केंद्र भारत के स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक खनिज सुरक्षा की ओर संक्रमण को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण, निष्कर्षण, पुनर्चक्रण और उन्नत सामग्री विकास में परिवर्तनकारी अनुसंधान शुरू करेंगे। यह पहल

घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने पर भी केंद्रित होगी।

Key Points:-

(i) उत्कृष्टता केंद्र (COE) के रूप में नामित तीन अनुसंधान एवं विकास (RND) प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद - खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान (CSIR-IMNT), भुवनेश्वर, ओडिशा; सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (NML), जमशेदपुर, झारखंड; और अलौह पदार्थ प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (NFTDC), हैदराबाद, तेलंगाना शामिल हैं। ये प्रयोगशालाएँ उच्च-मूल्य सामग्री विकास और अलौह निष्कर्षण नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

(ii) ये सात उत्कृष्टता केंद्र भारत के स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक खनिज सुरक्षा की ओर संक्रमण को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण, निष्कर्षण, पुनर्चक्रण और उन्नत सामग्री विकास में परिवर्तनकारी अनुसंधान शुरू करेंगे। यह पहल घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने पर भी केंद्रित होगी।

(iii) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्रों को सार्वजनिक-निजी मॉडल के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, जिसमें सरकारी सहायता, अनुसंधान एवं विकास संस्थान और औद्योगिक हितधारक शामिल होंगे। इन संस्थानों से निवेश आकर्षित करने, नवाचार को गति देने और महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करने की उम्मीद है।

6. ICAR-CMFRI वार्षिक रिपोर्ट 2024: भारत की समुद्री मछली पकड़ 2% घटकर 3.47 मिलियन टन रह गई और 8% की गिरावट के बावजूद गुजरात सबसे आगे।"



जुलाई 2025 में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (ICAR-CMFRI) ने अपनी "ICAR-CMFRI वार्षिक रिपोर्ट 2024" जारी की, जिसमें 2023 की तुलना में भारत की समुद्री मछली पकड़ में 2% की गिरावट का खुलासा किया गया। 2024 के लिए कुल पकड़ 3.47 मिलियन टन थी, जो क्षेत्रीय असमानताओं और प्रजाति-विशिष्ट उतार-चढ़ाव को उजागर करती है।

- 2024 में 754,000 टन समुद्री मछली पकड़ने के साथ गुजरात सबसे आगे रहा, उसके बाद 679,000 टन के साथ तमिलनाडु और 610,000 टन के साथ केरल का स्थान रहा। सूची में शीर्ष पर होने के बावजूद, भारत की कुल मछली पकड़ का 22% हिस्सा रखने वाले गुजरात में 2023 की तुलना में 8% की गिरावट दर्ज की गई।

- समुद्री प्रजातियों में, भारतीय मैकेरल की सबसे ज्यादा पकड़ हुई, जिसकी कुल मात्रा 2.63 लाख टन थी, उसके बाद ऑयल सार्डिन की 2.41 लाख टन। कुल पकड़ी गई मछलियों में पेलाजिक प्रजातियाँ 54% थीं, जो तलमज्जी मछलियों, क्रस्टेशियंस और मोलस्क पर उनके प्रभुत्व को दर्शाता है।

- रिपोर्ट में लेसर सार्डिन, पेनेड्ड श्रिम्प, एंकोवीज़ और ट्रूना जैसी प्रजातियों के आगमन में सकारात्मक रुझान देखा गया, जिनकी संख्या पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रही। हालाँकि, मैकेरल, थ्रेडफ़िन ब्रीम, रिबनफ़िश, नॉन-पेनेड्ड श्रिम्प और

सेफ़लोपोड्स जैसी प्रमुख प्रजातियों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।

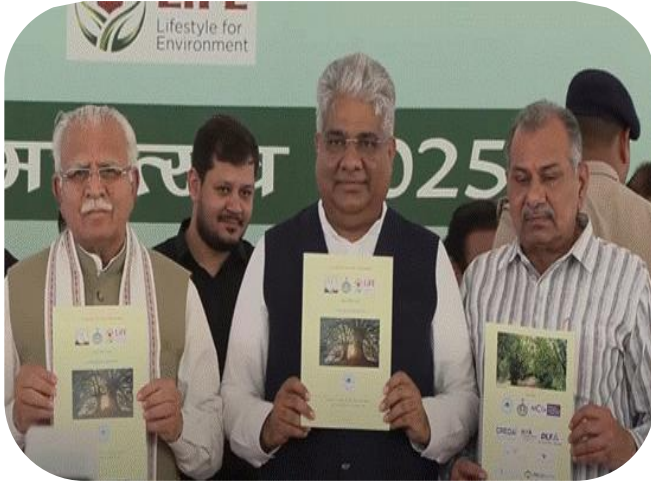
Key Points:-

(i) क्षेत्रीय स्तर पर, पूर्वी तट के राज्यों में मज़बूत वृद्धि दर्ज की गई, महाराष्ट्र में 47%, पश्चिम बंगाल में 35%, तमिलनाडु में 20% और ओडिशा में 18% की वृद्धि देखी गई। इसके विपरीत, कर्नाटक, गोवा जैसे पश्चिमी तट के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव में मछली पकड़ने की मात्रा में गिरावट देखी गई।

(ii) क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चला है कि मोटर चालित मत्स्य पालन क्षेत्र में, विशेष रूप से तमिलनाडु और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, 10 लाख टन की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालाँकि, कुल मत्स्य पकड़ में 76% योगदान देने वाले यंत्रीकृत क्षेत्र में लगभग 1.7 लाख टन की गिरावट देखी गई, जो परिचालन अक्षमताओं या संसाधनों की कमी का संकेत है।

(iii) ICAR-CMFRI ने राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादकता का आकलन करने के लिए 2024 में 2.5 लाख से ज़्यादा मत्स्य यात्राओं की निगरानी की। मशीनी जहाजों से प्रति यात्रा औसतन 2,959 किलोग्राम मछलियाँ पकड़ी गईं, जबकि पारंपरिक मछुआरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मोटर चालित नावों से प्रति यात्रा 174 किलोग्राम मछलियाँ पकड़ी गईं। गैर-मोटर चालित जहाज, जो अक्सर हाथ से चलाए जाते हैं, ने प्रति यात्रा केवल 41 किलोग्राम मछलियाँ पकड़ीं, जो विभिन्न मत्स्य प्रौद्योगिकियों के बीच उत्पादकता में भारी अंतर को दर्शाता है।

7. केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव और मनोहर लाल खट्टर द्वारा वन महोत्सव 2025 के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 'मातृ वन' शहरी वन पहल शुरू की गई।



2 अगस्त, 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के गुरुग्राम के अरावली पर्वतीय क्षेत्र में 'मातृ वन' पहल का शुभारंभ किया। एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत विकसित, 750 एकड़ की इस वन परियोजना का शुभारंभ हरियाणा वन विभाग द्वारा वन महोत्सव 2025 के एक भाग के रूप में किया गया।

- 'मातृ वन' पहल का शुभारंभ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) तथा विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संयुक्त रूप से किया। यह पहल वन महोत्सव 2025 का एक प्रमुख आकर्षण है, जो 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला भारत का वार्षिक वृक्षारोपण अभियान है, जिसकी शुरुआत 1950 में पूर्व कृषि मंत्री के. एम. मुंशी ने की थी।

- यह परियोजना एक थीम-आधारित शहरी वन अवधारणा है जिसका शीर्षक 'मातृ वन' है, जिसका अर्थ है "माँ का वन"। अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ में फैली इस पारिस्थितिक पहल का उद्देश्य पर्यावरणीय और सांस्कृतिक, दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करना है। इसकी परिकल्पना एक ऐसे अनूठे हरित क्षेत्र के रूप में की गई है जो भारत के सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पारिस्थितिक क्षेत्रों में से एक में

जैव विविधता संरक्षण, जन कल्याण और शहरी स्थिरता को बढ़ावा देता है।

- इस वन में समर्पित पारिस्थितिक और विषयगत क्षेत्र शामिल हैं, जैसे बोधि वाटिका (पवित्र अंजीर का बाग), बांस वाटिका (बांस प्रजातियों का उद्यान), अरावली अबोरिटम, पुष्प वाटिका (फूलों वाले पौधे), सुगंध वाटिका (सुगंधित पौधे), औषधीय पादप वाटिका, नक्षत्र वाटिका (राशि-आधारित पौधे), राशि वाटिका, कैक्टस उद्यान और तितली उद्यान। ये वनस्पति क्षेत्र आध्यात्मिक, औषधीय और सौंदर्यपरक पादप विविधता को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

Key Points:-

(i) मातृ वन परियोजना में अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिक पुनर्स्थापना भी शामिल है, जिसमें काबुली कीकर (प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा) जैसी आक्रामक प्रजातियों को हटाकर उनकी जगह ढाक और अमलताश जैसे देशी वृक्ष लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण प्रयासों का उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता को बहाल करना, स्थानीय वन्यजीव आवासों को बढ़ावा देना और क्षेत्र की पारंपरिक वनस्पतियों को पुनर्जीवित करना है, साथ ही हरित क्षेत्र को बढ़ाना और शहरी ऊष्मा द्वीपों को कम करना है।

(ii) जनभागीदारी इस पहल का एक प्रमुख घटक है। शहरी वनों का विकास कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) योगदानकर्ताओं, निवासी कल्याण संघों (RWAs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs), स्कूली छात्रों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के सहयोगात्मक प्रयासों से किया जाएगा, जिससे नागरिकों में पर्यावरणीय स्वामित्व को बढ़ावा मिलेगा।

(iii) सामुदायिक संपर्क और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, इस वन में सार्वजनिक सुविधाएँ शामिल होंगी जैसे कि प्रकृति पथ, साइकिलिंग ट्रैक, योग स्थल, बैठने के लिए गज़ेबो, चारों कोनों पर इको-पार्किंग

सुविधाएँ और उपचारित जल सिंचाई प्रणाली। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) के साथ भी जुड़ी हुई है और भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन प्रतिबद्धताओं और दीर्घकालिक जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों में प्रत्यक्ष योगदान देती है।

INTERNATIONAL

1. हांगकांग ने डिजिटल वित्त नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए चयनात्मक लाइसेंसिंग के साथ पूर्ण-रिजर्व स्टेबलकॉइन विनियामक ढांचा शुरू किया।



21 मई, 2025 को, हांगकांग विधान परिषद ने फ़िएट-संदर्भित स्टेबलकॉइन्स को विनियमित करने के लिए ऐतिहासिक स्टेबलकॉइन्स विधेयक पारित किया। यह व्यवस्था पूर्ण-आरक्षित समर्थन, सख्त मोचन अधिकार और हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण (HKMA) से लाइसेंस अनिवार्य करती है, जिससे यह क्षेत्र एक वैश्विक डिजिटल वित्त केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा।

● स्टेबलकॉइन अध्यादेश के तहत जो 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी है-किसी भी फ़िएट-संदर्भित स्टेबलकॉइन (हांगकांग डॉलर द्वारा समर्थित सहित) के जारीकर्ता को HKMA द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना आवश्यक है। लाइसेंसधारियों को जारी किए गए टोकन का 100% समर्थन बनाए रखना होगा, ग्राहक

संपत्तियों को अलग करना होगा, और अनुरोध पर सममूल्य पर मोचन सुनिश्चित करना होगा।

● जारीकर्ताओं को हांगकांग में निगमित होना चाहिए, न्यूनतम चुकता पूंजी (HK\$25 मिलियन या जारी किए गए स्टेबलकॉइन मूल्य का 1%) बनाए रखना चाहिए, मज़बूत धन-शोधन-रोधी (AML/CFT) प्रोटोकॉल लागू करने चाहिए, और मज़बूत जोखिम-प्रबंधन एवं शासन मानदंडों का पालन करना चाहिए। इसमें आवधिक ऑडिट और पारदर्शी प्रकटीकरण शामिल हैं।

Key Points:-

(i) HKMA ने 29 जुलाई, 2025 को अंतिम दिशानिर्देश जारी किए - जिसमें पर्यवेक्षण, AML/CFT और संक्रमणकालीन नीतियां शामिल हैं। आवेदन अगस्त-सितंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे, पहला लाइसेंस 2026 की शुरुआत में मिलने की उम्मीद है, शुरुआत में संख्या सीमित होगी।

(ii) यह नियामक ढांचा हांगकांग को स्थिर मुद्रा पर्यवेक्षण में यूरोपीय संघ (MiCA) और अमेरिका जैसे समकक्षों से आगे रखता है- विशेष रूप से * दिवालियापन दूरस्थता संरक्षण, मोचन अधिकार प्रवर्तन और वैश्विक स्तर पर एचके डॉलर समर्थित जारीकर्ताओं पर बाह्यक्षेत्रीय अधिकार के मामले में।

(iii) नई लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत, जुलाई 2025 में हांगकांग में सूचीबद्ध फिनटेक कंपनियों ने स्टेबलकॉइन और ब्लॉकचेन भुगतान प्लेटफ़ॉर्म बनाने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की राशि जुटाई। हांगकांग के विनियमित फिनटेक रोडमैप के लिए निवेशकों का उत्साह बढ़ने के साथ ही निवेश में तेज़ी आई।

2. भारत 2024 में विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनकर उभरेगा और 241 मिलियन यात्रियों को संभालेगा।



2024 में, भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 24.1 करोड़ यात्रियों को परिवहन करते हुए, जापान को पीछे छोड़ते हुए, दुनिया का पाँचवाँ सबसे बड़ा विमानन बाज़ार बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) की नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी (WATS) रिपोर्ट में इस उपलब्धि का खुलासा हुआ है।

- भारत की हवाई यात्रियों की संख्या में साल-दर-साल 11.1% की वृद्धि हुई है, जो 2024 में 241 मिलियन तक पहुंच गई है। इस वृद्धि ने भारत को जापान से आगे निकलने में सक्षम बनाया, जिसने 18.6% वार्षिक वृद्धि के साथ 205 मिलियन यात्रियों को संभाला, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर आ गया।

- IATA की 2024 WATS रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका (876 मिलियन यात्री) शीर्ष स्थान पर रहा, उसके बाद चीन (741 मिलियन), यूनाइटेड किंगडम (261 मिलियन), स्पेन (241 मिलियन) और भारत पांचवें स्थान पर रहा।

Key Points:-

(i) मुंबई-दिल्ली हवाई गलियारा 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जोड़ों में से एक होगा, जो 5.9 मिलियन यात्रियों को परिवहन करेगा - जो वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे व्यस्त मार्ग है।

(ii) बढ़ती यात्री मांग ने भारत में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा दिया है। 2025

की शुरुआत तक, सरकार ने वित्त वर्ष 2020-25 की विमानन विस्तार योजना के तहत नियोजित पूंजीगत व्यय का 91% से अधिक हासिल कर लिया है, जिसमें नए हवाई अड्डों का निर्माण और मौजूदा सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

(iii) यह उपलब्धि भारत की तेजी से बढ़ती घरेलू विमानन मांग को उजागर करती है और 2047 तक वैश्विक विमानन केंद्र बनने की इसकी महत्वाकांक्षा को पुष्ट करती है। हालांकि, एयरलाइन क्षमता की कमी, बुनियादी ढाँचे में अंतराल और नियामक बाधाएं प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं।

ECONOMY & BUSINESS

1. BIAL ने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 9,000 करोड़ रुपये मूल्य का भारत का सबसे बड़ा गैर-सूचीबद्ध NCD जारी किया।



अगस्त 2025 में, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (BIAL), जो कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संयुक्त उद्यम (JV) संचालक है, ने भारत के विमानन क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा अपसूचिबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) निर्गम सफलतापूर्वक पूरा किया। इस प्रक्रिया में कुल ₹9,000 करोड़ जुटाए गए, जो ऋण पुनर्वित्त और भविष्य की अवसंरचना विस्तार योजनाओं में उपयोग होंगे।

● कुल ₹9,000 करोड़ की राशि को दो किश्तों में जुटाया गया है—₹4,362 करोड़ की पहली किश्त 25 जुलाई 2025 को पूरी हो गई, जबकि शेष ₹4,638 करोड़ की दूसरी किश्त अक्टूबर 2025 की शुरुआत में पूरी होने की योजना है।

● भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट्स (SBICAPS) ने इन गैर-सूचीबद्ध NCD को जारी करने के लिए एकमात्र प्रबन्धक के रूप में कार्य किया, जो भारत के वित्तीय बाजारों में मजबूत संस्थागत समर्थन और विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है।

● 15 वर्षों की पुनर्वित्त अवधि BIAL को परिचालन पूंजी को संरक्षित करने और हवाई अड्डे के आगामी विस्तार कार्यों के लिए संसाधनों को रणनीतिक रूप से आवंटित करने में मदद करेगी।

Key Points:-

(i) इस NCD निर्गम से BIAL को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ होंगे। AAA क्रेडिट रेटिंग, MCLR-आधारित ऋण से फिक्स्ड ब्याज दर में बदलाव और विस्तारित परिपक्वता अवधि जैसे कारकों के कारण उधारी लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।

(ii) ₹9,000 करोड़ की यह राशि न केवल मौजूदा उच्च लागत वाले ऋणों के पुनर्वित्त के लिए उपयोग होगी, बल्कि केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के भविष्य के बुनियादी ढांचा विस्तार कार्यों को भी गति देगी, जिससे यह भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक के रूप में अपनी क्षमता और कार्यक्षमता बढ़ा सकेगा।

2. मौसम और कीटों के हमलों के कारण जून 2025 में भारत का चाय उत्पादन 9% घटकर 133.5 मिलियन किलोग्राम रह गया।



जून 2025 में भारत का चाय उत्पादन जून 2024 की तुलना में 9 प्रतिशत घटकर 133.5 मिलियन किलोग्राम रह गया। खराब मौसम, अत्यधिक वर्षा, उच्च तापमान और व्यापक कीट संक्रमण के कारण हुई इस गिरावट ने उत्तर और दक्षिण भारत के दोनों प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों को प्रभावित किया।

● उत्तर भारत का चाय उत्पादन लगभग 7.44 प्रतिशत घटकर 112.51 मिलियन किलोग्राम रह गया, जबकि दक्षिण भारत में 16.7 प्रतिशत की भारी गिरावट आई और उत्पादन केवल 20.99 मिलियन किलोग्राम रहा। केरल (-31%), तमिलनाडु (-11%) और कर्नाटक जैसे राज्यों में भारी गिरावट देखी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में संकट का संकेत मिलता है।

● असम में, गिरावट लगभग 10 प्रतिशत रही, जबकि कछार क्षेत्र का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा। पश्चिम बंगाल में, दुआर्स क्षेत्र में 10.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि तराई और दार्जिलिंग क्षेत्रों में मामूली वृद्धि देखी गई, जो समग्र संकुचन के बीच स्थानीय भिन्नताओं को उजागर करती है।

● उत्तर बंगाल के दुआर्स और तराई क्षेत्रों में चाय बागानों में उत्पादन में 0.4 प्रतिशत से 25.5 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण बेमौसम बारिश, सामान्य से अधिक तापमान (36.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना) और हरी मक्खी, थ्रिप्स और लाल मकड़ी के कण जैसे कीटों का

प्रकोप है, जो फफूंद और जीवाणु संक्रमण के कारण बढ़ जाता है।

Key Points:-

(i) भारतीय चाय संघ (ITA) के अनुसार, 2025 में अनियमित जलवायु परिवर्तन—जिसमें सूखा, 2°C तापमान वृद्धि और कम वर्षा शामिल है—ने चाय की फसल की स्थिति को और खराब कर दिया है। जुलाई 2025 की फसल में भी 15 से 20 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, जिससे 2024 में पहले हुई कमी से उद्योग पर दबाव और बढ़ जाएगा।

(ii) उत्पादन में भारी गिरावट ने डाउनस्ट्रीम दबाव बढ़ा दिया है: अप्रैल और जुलाई के बीच असम में सीटीसी और डस्ट किस्मों की चाय की नीलामी कीमतों में 7 प्रतिशत और दुआर्सा/तराई (पश्चिम बंगाल) में 9.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। बढ़ते चाय आयात (2024 में 82 प्रतिशत की वृद्धि) ने घरेलू मूल्य प्राप्ति को और कम कर दिया है, जिससे बागान मालिकों और उत्पादकों दोनों पर दबाव बढ़ रहा है।

3. जुलाई 2025 में भारत का पाम ऑयल आयात 10% गिर गया जबकि सोया ऑयल शिपमेंट 38% बढ़कर तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।



जुलाई 2025 में, भारत का पाम तेल आयात 10% घटकर 8,58,000 मीट्रिक टन रह गया, जिसका मुख्य कारण अनुबंध रद्द होना था। इस बीच, सोया तेल का

आयात 38% बढ़कर 4,95,000 टन हो गया, जो तीन वर्षों में सबसे अधिक मासिक स्तर था, जिसकी वजह शिपमेंट में देरी और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण था।

● भारतीय रिफाइनरियों ने बेंचमार्क मलेशियाई पाम ऑयल वायदा में कीमतों में भारी उछाल का हवाला देते हुए जुलाई और सितंबर के बीच डिलीवरी के लिए लगभग 65,000 टन पाम ऑयल के अनुबंध रद्द कर दिए। इसके परिणामस्वरूप जून के स्तर से आयात में 10% की गिरावट आई।

● सोया तेल का आयात महीने-दर-महीने 38% बढ़कर जुलाई में 495,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया—जो तीन सालों में सबसे ज़्यादा है। यह उछाल प्रतिस्पर्धी सीआईएफ कीमतों और जून से पहले से विलंबित शिपमेंट के जारी होने से प्रेरित था।

Key Points:-

(i) पाम तेल से सोया तेल की ओर बदलाव, वैश्विक मूल्य गतिशीलता के प्रति रिफाइनरों की प्रतिक्रिया को दर्शाता है: पाम तेल अपेक्षाकृत महंगा हो गया, जबकि सोया तेल अपनी कम लागत के कारण ध्यान आकर्षित कर रहा था। इससे खाद्य तेल आयात मिश्रण में सोया तेल के पक्ष में महत्वपूर्ण बदलाव आया।

(ii) हालाँकि पाम तेल का आयात एक महीने पहले ही 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन कम स्टॉक और मौसमी माँग के कारण रिफाइनर कंपनियों को अनुबंध रद्द करने और अपनी उत्पादन क्षमता को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोया तेल के आयात के ज़रिए स्टॉक की पूर्ति ने भी जुलाई में भारत के खाद्य तेल के कुल उपभोग में मामूली वृद्धि में योगदान दिया।

(iii) भारत की पाम तेल खरीद में गिरावट ने मलेशियाई और इंडोनेशियाई निर्यातकों पर दबाव बढ़ा दिया है, जिससे संभवतः स्टॉक बढ़ सकता है। इस बीच, सोया तेल के आयात में वृद्धि ने अमेरिकी सोया तेल की कीमतों को समर्थन दिया है। विश्लेषकों का अनुमान है कि आने वाले महीनों में कीमतों के

अंतर कम होने के साथ पाम तेल की मांग में फिर से तेजी आएगी।

AWARDS

1. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पुणे में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



अगस्त 2025 में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अध्यक्ष हैं, को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समारोह महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया और भारत के सड़क अवसंरचना विकास और परिवहन क्षेत्र में पारदर्शी एवं कुशल शासन को बढ़ावा देने में नितिन गडकरी के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी गई।

● लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक है, जिसे स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए स्थापित किया गया था, जिन्हें व्यापक रूप से लोकमान्य तिलक के रूप में जाना जाता है।

● यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि 1 अगस्त को उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

● नितिन गडकरी को यह सम्मान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और स्मार्ट परिवहन में परिवर्तनकारी परियोजनाओं का नेतृत्व करने के लिए दिया गया है, जो भारत सरकार के विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे के लक्ष्य के अनुरूप है। यात्रा समय को कम करने, रसद दक्षता में सुधार लाने और देश भर में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने में उनका काम महत्वपूर्ण रहा है।

Key Points:-

- (i) यह पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा 1983 में स्थापित किया गया था और अब भारत के विकास में योगदान देने वालों के प्रति राष्ट्रीय कृतज्ञता का प्रतीक बन गया है। इसके अंतर्गत ₹1 लाख का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और पुणे में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है।
- (ii) पिछले कुछ वर्षों में, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार कई प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, जो उनके ऐतिहासिक महत्व और प्रतिष्ठा को दर्शाता है।
- (iii) 2025 में आयोजित होने वाला 43वाँ संस्करण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रीय परिवर्तन को गति देने वाले नेताओं को मान्यता देने के निरंतर महत्व को दर्शाता है। नितिन गडकरी को मिले इस सम्मान को भारत के बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में उनके व्यावहारिक, प्रौद्योगिकी-संचालित और सतत विकास दृष्टिकोण के प्रति सम्मान के रूप में देखा जा रहा है।

IMPORTANT DAYS

1. राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस 2025 सभी आयु समूहों में मस्क्युलोस्केलेटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 4 अगस्त को मनाया गया।

NATIONAL BONE AND JOINT DAY 2025 OBSERVED ON AUGUST 4 TO PROMOTE MUSCULOSKELETAL HEALTH ACROSS ALL AGE GROUPS



भारत हर साल 4 अगस्त को राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस मनाता है, जिसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए मज़बूत हड्डियों और जोड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस मस्क्युलोस्केलेटल विकारों का शीघ्र पता लगाने और उनकी रोकथाम पर भी केंद्रित है, और दीर्घकालिक हड्डियों और जोड़ों की जटिलताओं को कम करने के लिए एक स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करता है।

● भारतीय ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन (IOA) हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2012 से इस दिवस का आयोजन करता आ रहा है। यह दिन आईओए के चार्टर-हस्ताक्षर दिवस का भी प्रतीक है, जिसका आधिकारिक गठन 1971 में हुआ था, जिससे 4 अगस्त चिकित्सा जगत में दोहरा मील का पत्थर बन गया।

● राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस 'अस्थि एवं जोड़ सप्ताह' की शुरुआत के रूप में कार्य करता है, जो 4 अगस्त से 10 अगस्त तक मनाया जाता है। इस सप्ताह में स्वास्थ्य शिविर, शैक्षिक कार्यक्रम और मस्क्युलोस्केलेटल स्वास्थ्य को बनाए रखने और आर्थोपेडिक बीमारियों को रोकने के बारे में जन जागरूकता अभियान शामिल हैं।

● यह अभियान स्वस्थ जीवनशैली के महत्व पर ज़ोर देता है, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, और धूम्रपान व शराब से परहेज, जो हड्डियों की मज़बूती और जोड़ों के लचीलेपन को सीधे प्रभावित करते हैं। ये आदतें युवावस्था में 25-30 वर्ष की आयु से पहले पीक बोन मास (PBM) बनाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

Key Points:-

- (i) हड्डियाँ आंतरिक अंगों की सुरक्षा, शरीर की संरचना को सहारा देने और गतिशीलता को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विकास काल के दौरान, विशेष रूप से बच्चों और किशोरों में, हड्डियाँ उच्च चयापचय गतिविधि से गुजरती हैं, जिससे पर्याप्त पोषक तत्वों का सेवन आवश्यक हो जाता है ताकि जीवन में आगे चलकर अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बनने वाली कमियों को रोका जा सके।
- (ii) यह दिवस सामान्य मस्क्युलोस्केलेटल विकारों पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, जो कम अस्थि घनत्व और नाजुक हड्डियों से जुड़ी एक प्रगतिशील स्थिति है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया का सबसे आम रूप है, जो उपास्थि के टूटने, जोड़ों में अकड़न और पुराने दर्द से चिह्नित होता है - विशेष रूप से हाथों, कूल्हों और घुटनों को प्रभावित करता है।
- (iii) मस्क्युलोस्केलेटल विकार गतिशीलता, उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जिससे अक्सर दीर्घकालिक दर्द और विकलांगता होती है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को निवारक देखभाल, शीघ्र हस्तक्षेप और उचित निदान के बारे में शिक्षित करना है ताकि व्यक्तियों और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दोनों पर इन विकारों का बोझ कम से कम हो।

2. भारतीय अंगदान दिवस 2025 भारत के पहले मृतक अंग प्रत्यारोपण को चिह्नित करने के लिए 3 अगस्त को मनाया गया।



भारतीय अंगदान दिवस (IODD) देश के पहले सफल मृतक अंग प्रत्यारोपण के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 3 अगस्त को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के अंतर्गत राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) द्वारा किया जाता है। 2025 में मनाया जाने वाला यह राष्ट्रीय आयोजन अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

● भारतीय अंगदान दिवस 2025, 3 अगस्त को मनाया गया और इस आयोजन का 15वाँ आधिकारिक उत्सव मनाया गया। यह तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के पहले सफल हृदय प्रत्यारोपण की वर्षगांठ का प्रतीक है, इसलिए इसे 27 नवंबर (जो 2022 तक लागू था) से हटाकर 2023 से 3 अगस्त कर दिया गया है।

● यह कार्यक्रम NOTTO के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के अधीन कार्य करता है। IODD 2025 का मुख्य समारोह भीम हॉल, डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (DAIC), नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों, चिकित्सा पेशेवरों और अंगदान कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

● IODD को मूल रूप से NOTTO द्वारा 2010 में लॉन्च किया गया था और 2023 में बदलाव होने तक हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता था। 3 अगस्त को बदलाव भारत के पहले हृदय प्रत्यारोपण की तारीख के साथ पालन को संरेखित करने के लिए किया गया था, जो देश के चिकित्सा इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी और 3 अगस्त 1994 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIMS), नई दिल्ली में हुई थी।

Key Points:-

(i) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। समारोह के दौरान, उन्होंने अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया। उन्होंने जन जागरूकता के महत्व और नैतिक एवं सुलभ प्रत्यारोपण सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर भी ज़ोर दिया।

(ii) समारोह के दौरान दो नई जागरूकता पुस्तिकाएँ जारी की गईं। एक पुस्तिका आम जनता और छात्रों के लिए बनाई गई है और आयुर्वेद एवं योग के माध्यम से अंग स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। दूसरी पुस्तिका अंगदान और प्रत्यारोपण में राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित है, और दोनों का उद्देश्य राष्ट्रीय अंगदान आंदोलन में जन सहभागिता और भागीदारी को बढ़ाना है।

(iii) भारतीय चिकित्सा इतिहास में 3 अगस्त का महत्व 1994 में एम्स, नई दिल्ली में किए गए देश के पहले सफल हृदय प्रत्यारोपण से जुड़ा है। इस सर्जिकल सफलता ने भारत के अंग प्रत्यारोपण ढाँचे की नींव रखी, जो NOTTO के नेतृत्व में निरंतर विकसित हो रहा है और मृतक दाता कार्यक्रमों के माध्यम से अनगिनत लोगों की जान बचाने में योगदान दे रहा है।

OBITUARY

1. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया।



झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) पार्टी के संस्थापक, वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन का 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनका इलाज चल रहा था और उन्हें सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

- शिबू सोरेन, जिन्हें दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है, एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और कई बार सांसद चुने गए। वे पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री भी थे।

- शिबू सोरेन किडनी की समस्या और मधुमेह से पीड़ित थे और उनके निधन से लगभग डेढ़ महीने पहले उन्हें स्ट्रोक भी हुआ था। वे सर गंगा राम अस्पताल में जीवन रक्षक प्रणाली पर थे और 4 अगस्त 2025 को सुबह 8:56 बजे उनका निधन हो गया।

Key Points:-

(i) झारखंड सरकार ने 4 से 6 अगस्त तक तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। सभी झंडे आधे झुके रहेंगे और आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए

गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें आदिवासी अधिकारों की एक सशक्त आवाज़ बताया।

(ii) शिबू सोरेन के पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "गुरुजी नहीं रहे। मैं आज शून्य हो गया हूँ।" झारखंड विधानसभा भी इस वयोवृद्ध नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए समय से पहले ही तैयार हो गई। राज्य भर से बड़ी संख्या में लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए।

(iii) शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर रांची लाया गया, जहाँ हजारों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने आए। देश भर से कई सामाजिक और राजनीतिक नेता मौजूद थे। उम्मीद है कि उनकी विरासत को उनके बेटे हेमंत सोरेन और बहू कल्पना सोरेन आगे बढ़ाएँगे, जो झामुमो के सक्रिय नेता हैं।

Static GK

Indian Orthopaedic Association (IOA)	अध्यक्ष : डॉ. अजीत शिंदे	मुख्यालय: नई दिल्ली
National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)	अध्यक्ष: शाजी के.वी.	मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
Ministry of Mines (MoM)	केंद्रीय मंत्री: गंगापुरम (जी.) किशन रेड्डी	मुख्यालय: नई दिल्ली
Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI);	निर्देशक- ग्रिनसन जॉर्ज	मुख्यालय - कोच्चि, केरल
MoRTH	केंद्रीय मंत्री: नितिन गडकरी	मुख्यालय: नई दिल्ली
Jharkhand	राजधानी: रांची	राज्यपाल: संतोष गंगवार
International Air Transport Association (IATA)	महानिदेशक: विली वॉल्श	मुख्यालय: मॉन्ट्रियल, कनाडा